

देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे पैदा करेगा 450 मेगावाट ऊर्जा

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर पार्क के लिए आई 17 कंपनियों, लागत घटाने के लिए मुफ्त जमीन देने पर भी विचार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। देश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे में तब्दील होने जा रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 450 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेगा। 296 किमी लंबे ई वे के दोनों तरफ 2447 एकड़ में सोलर पार्क विकसित करने के लिए देश-दुनिया की 17 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सौर ऊर्जा की लागत घटाने के लिए कंपनियों की मांग को देखते हुए उन्हें मुफ्त जमीन दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने अभी 15 हजार रुपये एकड़ का रेट तय किया है। ये जानकारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित होने वाले सोलर पार्क के लिए पहली बार आयोजित वर्कशाप में दी गई।

कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताई चुनौतियां

कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि इतने लंबे एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल की सुरक्षा चुनौती है। इनकी चोरी या तोड़फोड़ हो सकती है। इनकी देखरेख के लिए सिक््योरिटी सिस्टम पर भी भारी खर्च आएगा। सोलर पैनल लगाने और सौर ऊर्जा स्टोर करने पर काफी खर्च बहुत होगा। एक्सप्रेसवे पर चौबीस घंटे वाहन दौड़ने के कारण पैनलों पर जमा होने वाली धूल हटाना भी चुनौती है। ग्रिड से जोड़ने पर भी लागत बहुत आएगी। इन चिंताओं का समाधान करते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सोलर पैनलों के दोनों तरफ फेंसिंग की जाएगी। सुरक्षा के लिए यूपीडा और मॉटेनेंस कंपनी के चार वाहन चौबीस घंटे गश्त पर रहेंगे। ग्रिड से दूरी 50 किलोमीटर तक है, जिसके लिए सब्सिडी का प्रावधान है। सोलर पैनलों की सफाई के लिए हाईटेक सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया। लागत कम करने के लिए कहा कि 15 हजार रुपये एकड़ का रेट हटाया जा सकता है। इसकी भरपाई यूपीडा को प्रति यूनिट बिजली उत्पादन से मिलने वाली हिस्सेदारी से हो सकती है। अभी यूपीडा ने 7 पैसे प्रति यूनिट की न्यूनतम सीमा तय की है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) और टीएचडीसी इंडिया लि. के संयुक्त उद्यम टुस्को के सीईओ मनोज सरदाना ने बताया कि

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 14 नोड्स पर सोलर पार्क स्थापित होंगे। ये 18 महीने के अंदर शुरू होगा। इस पर करीब 2000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। एक महीने में

रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन सोलर पार्क से एक्सप्रेसवे पर वायरलैस ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

सोलर पार्क को छह हिस्से में बांटा गया है। प्रत्येक हिस्सा 50 किलोमीटर का होगा। एक कंपनी चाहे तो 50 किलोमीटर का एक पॉकेट या इससे ज्यादा के लिए आवेदन कर सकती है। कार्यशाला में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निवेशकों से कहा कि उनकी हर समस्या को दूर किया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर और विशेष सचिव सुजीत कुमार मौजूद थे।